और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी कभी भी चार बैठकें नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाषा के प्रचार, विकास और प्रयोग के लिये टेलीप्रिन्टर, टैलेक्स कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों आदि जैसे आवश्यक यंत्रों की इस मंत्रालय में व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले ग्यारह वर्षों से पूरे नहीं हो सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन 13-12-1983 को किया गया था । उक्त समिति की दो बैठकें 1984 के दौरान आयोजित की गई । आठवीं लोक सभा/राज्य सभा के नये सदस्यों के चुनाव तथा कुछ नये मंत्रालयों/विभागों के सृजन के फलस्वरूप उक्त समिति का जुलाई, 1985 में पुनर्गठन किया गया । समिति की अगली बैठक 29 नवम्बर, 1985 को आयोजित की जा रही है ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपिक तथा देवनागरी टाइपराइटर उपयुक्त संख्या में हैं और इस विभाग में राजभाषा का विकास पिछड़ नहीं रहा है, परन्तु इस मंत्रालय का वैज्ञानिक स्वरूप होने के कारण, इस में हिन्दी में इतना कार्य नहीं उत्पन्न होता कि हिन्दी कम्प्यूटरों, टेलीप्रिन्टरों, टेलैक्स मशीनों को खरीदने का औचित्य ठहराया जा सके ।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए हिन्दी का प्रयोग

1279. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार राजभाषा अधिनियम की तथा हिन्दी के प्रचार के वार्षिक कार्यक्रम को अन्तरिक्ष विभाग में किस प्रकार लागू करने का विचार रखती है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटिल : (क) अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिये अंग्रेजी के अलावा, हिन्दी का भी यथासंभव प्रयोग किया जाता है

(ख) राजभाषा अधिनियम और हिन्दी के प्रचार के वार्षिक कार्यक्रम को अन्तरिक्ष विभाग में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है ।

Indigenous development - of AW ACS

1280. SHRI KISHOR MEHTA:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to develop its own AW ACS in view of the reluctance of western countries to give technological assistance for manufacturing them in India; and

(b) what steps have been taken so far in this regard and how much time is likely to be taken to develop them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SHRI ARUN SINGH): (a) Government has initiated necessary action to acquire AWACS capability jmdigenously.

fb-) It will not be appropriate to discuss further details because of security reasons.